vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. RAJHIN/2019/77486

_vishikhamedia/ vishikhamedia/

तीर निशाने पर

विशिखा

मूल्यः 25 रूपये

वर्ष:07 अंक:3 मार्च 2025 पृष्ठ:32

राजस्थान संस्करण

vishikhamedia vishikhamedia.in

अमेरिका अपने नियम कानून से चलेगा

अवैध भारतीय अप्रवासियों

को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा अमेरिकी विमान

भारत को भी घुसपैठियों से ऐसे ही निपटना होगा

विशिखा

न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

‘गोल्ड कार्ड’ खरीदो और अमेरिका की आजीवन नागरिकता पाओ

अमेरिका में बसने के लिए लेना होगा 50 लाख डॉलर की कीमत का ‘गोल्ड कार्ड’, ट्रंप अमीर विदेशी निवेशकों के माध्यम से करेंगे अमेरिका में नौकरियों का सृजन 09

10 | अमेरिका अपने नियम कानून से चलेगा, भारत को भी घुसपैठियों से ऐसे ही निपटना होगा

12 | यूपी की नई आबकारी नीति, एक तीर से कई निशाने

13 | अखिलेश पर भारी पड़ रहा है महाकुंभ का विरोध

16 | १९८४ के सिख विरोधी दंगो के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद

18 | भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार आईआईटी मद्रास कर रहा है निर्माण

20 | योगी ने किया महाकुंभ का समापन, सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया

23 | यूपीः आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनेंगे होटल, थीम पार्क और रिजॉर्ट

24 | अगले २० सालों में ८० प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं कैंसर से मौत के मामले

26 | यूक्रेन भड़का सकता है तीसरा विश्व युद्ध-ट्रंप

28 | एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के खतरे को ८० प्रतिशत तक कम सकती है

विशिखा
तीन निशाने पर...

विशिखा
तीर निशाने पर

अंक: 3 वर्ष:07, मार्च 2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

विशिखा
तीन निशाने पर...

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** 191/56 (जानकी देवी स्कूल के पास) सेक्टर–19, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर– 302033 राजस्थान के लिए प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई–मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व–लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई–मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
’किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
’पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेवसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात, आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए इस भव्य, दिव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्म के करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। यानि देश के करीबन 50 प्रतिशत भारतीयों ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर जब श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ के पार पहुंच गई। जिससे यह महाकुंभ अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया।

इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हों। यदि इसे विभिन्न देशों की जनसंख्या से तुलना करें, तो यह अमेरिका की दोगुनी, पाकिस्तान की ढाई गुना और रूस की चार गुना से अधिक आबादी के बराबर है। जापान की पांच गुना, यूके की दस गुना और फ्रांस की पंद्रह गुना आबादी के बराबर श्रद्धालुओं ने यहां संगम में पवित्र स्नान किया है।

सनातन धर्मावलंबियों की बात करें, तो देश के 60 प्रतिशत से अधिक और विश्व के लगभग 55 प्रतिशत श्रद्धालु इस पावन महाकुंभ के साक्षी बने। इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी भी आयोजन में पहले कभी इतने लोग नहीं जुटे हैं। 45 दिनों के भीतर एक अस्थायी शहर महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक रही है। भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

महाकुंभ में आये श्रद्धालुओं की संख्या यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदों को पार कर गई। उन्होंने पहले 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन 11 फरवरी तक ही यह संख्या पार हो गई थी, और इसके 10 दिन बाद ही 22 फरवरी को 60 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। महाशिवरात्रि के दिन 65 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर महाकुंभ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ये सच है कि महाकुंभ के इस आयोजन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत ऊँचा हो गया है, जिसे हर किसी के लिए पाना संभव नहीं है।

शेष फिर....

प्रदर्शन में शामिल होने पर जेएनयू प्रशासन ने छात्रों से 18 लाख रुपए जुर्माना वसूला

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने पिछले छह वर्षों में विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने और विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों से 18 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना जेएनयू के स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस से लगभग चार गुना अधिक है।

यूजी पाठ्यक्रमों की फीस कितनी है?

जेएनयू भारत के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और यह एक सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान है। यहां अधिकांश स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस मात्र 410 रुपये है। छप्स्थ के आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक 10 स्नातक पाठ्यक्रमों में 1,209 छात्रों ने दाखिला लिया था। मौजूदा छात्रों की संख्या और उपलब्ध पाठ्यक्रमों के आधार पर कुल फीस 4,95,690 रुपये आंकी गई है।

विभिन्न वर्षों में लगाया गया जुर्माना

2019: 3.5 लाख रूपये
2020: 40,000 रूपये
2021: 2.4 लाख रूपये
2022: 3.8 लाख रूपये
2023: सीपीओ मैनुअल के अधिसूचित होने के बाद जुर्माना 5.5 लाख तक पहुंच गया, जबकि विश्वविद्यालय ने 2.5 लाख वसूले।

कैंपस के 100 मीटर दायरे में धरना प्रतिबंधित

2023 में जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में होने वाले लगातार प्रदर्शनों पर नियंत्रण के लिए नए नियम लागू किए। इन नियमों के तहतः

- कैंपस के 100 मीटर के दायरे में धरना देने या पोस्टर लगाने पर 20,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
- गंभीर मामलों में विश्वविद्यालय से निष्कासन का प्रावधान भी रखा गया है।
- किसी भी राष्ट्र–विरोधी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर छात्रों पर 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

होस्टल फीस वृद्धि को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन

2019 में जेएनयू प्रशासन द्वारा होस्टल फीस बढ़ाए जाने के बाद छात्रों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। जब छात्रों ने वीसी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया, तो कई छात्रों को नोटिस जारी किए गए। एक अन्य मामले में बाहरी छात्रों को होस्टल में प्रवेश देने और पार्टी करने के आरोप में छात्रों पर 1.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, हालांकि विश्वविद्यालय ने ऐसे किसी भी जुर्माने से इनकार किया।

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जेएनयू

जेएनयू उन विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां कम फीस में उच्च शिक्षा मिलती है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र यहां बड़ी संख्या में प्रवेश लेते हैं।
लेकिन हाल के वर्षों में, शिक्षा के अलावा अन्य मुद्दों पर भी छात्रों की सक्रियता बढ़ी है, जिसमें सुविधाओं की कमी और फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रमुख हैं।

छात्रों की मांग, जुर्माना वापस लिया जाए

लंबे समय से जेएनयू छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन से जुर्माना रद्द करने और सीपीओ मैनुअल को वापस लेने की मांग कर रहा है। छात्रों का कहना है कि यह मैनुअल उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है और असहमति की संस्कृति को रोकता है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। जेएनयू वीसी के अनुसार, ये नियम पहले से मौजूद थे, लेकिन 2023 में कानूनी रूप से संरचित और अधिसूचित किए गए।

अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा अमेरिकी विमान

अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार दोपहर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। जानकारी के अनुसार, इस विमान में कुल 104 निर्वासित भारतीय थे और यह दोपहर लगभग 1:55 बजे लैंड हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें पंजाब से 30, हरियाणा और गुजरात से 33-33, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से तीन-तीन तथा चंडीगढ़ से दो लोग थे। निर्वासित भारतीयों में 18 वर्ष से कम उम्र के 12 बच्चे और लगभग 24 महिलाएं भी शामिल थीं। अब तक डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अवैध प्रवासियों को सैन्य विमानों से उनके देशों में वापस भेजा है।

बुधवार को अमेरिकी वायु सेना का विमान कथित रूप से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर पंजाब के अमृतसर पहुंचा। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि हालांकि पूरी जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन यह स्पष्ट है कि अमेरिका अपने सीमा और आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा, अब तक की गई कार्रवाइयों से यह साफ संदेश जाता है कि अवैध प्रवासियों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। सीबीएस न्यूज के अनुसार, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन कुछ प्रवासी बंदियों को रिहा कर

रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के दौरान गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने से हिरासत केंद्र अपनी अधिकतम क्षमता पार कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी जेलों में करीब 42,000 प्रवासी बंदी हैं।

हथकड़ी अपमानजनक व्यवहार

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर, एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। उन्होंने दिसंबर 2013 की उस घटना को याद किया जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और स्ट्रिप सर्च (कपड़े उतरवाकर तलाशी) की गई थी। खेड़ा ने कहा कि तब यूपीए सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। डॉ. मनमोहन सिंह ने इस घटना को षनिंदनीयष बताया था, और भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली थीं, जिनमें राजनयिकों के लिए खाद्य पदार्थों और शराब के रियायती आयात की अनुमति भी शामिल थी।

विदेश मंत्रालय का बयान

24 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका या दुनिया के किसी भी हिस्से में बिना उचित दस्तावेजों के रहने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ष्हम अवैध अप्रवास का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है।ष उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी देश में तय समय से अधिक समय तक रह रहा है या उचित दस्तावेजों के बिना वहां मौजूद है, तो सरकार उनकी नागरिकता की पुष्टि करने के बाद उनकी वापसी की प्रक्रिया में मदद करेगी।

डोंकी रूट के जरिए पहुंचे थे ये लोग

अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए ये भारतीय डोंकी रूट यानी गैर–कानूनी तरीकों से वहां पहुंचे थे। उन्हें एजेंटों के जरिए पनामा, मैक्सिको आदि के जंगलों के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करवाया गया था। इन एजेंटों की फीस प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपये तक होती है। इस सफर के दौरान कई लोग जंगलों में भूख और प्यास से दम तोड़ देते हैं और अमेरिका तक पहुंच ही नहीं पाते।

विमान में टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं खोली हथकड़ी व बेड़ियां

भारत आए कई पुरुषों और महिलाओं ने अधिकारियों को बताया कि ट्रैवल एजेंटों ने उनके साथ धोखाधड़ी की। कई लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और अपने परिवार को यह बताने से बच रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ।

अमेरिकी सैन्य विमान सी–17 ग्लोबमास्टर 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। भारत लौटे कई पुरुषों और महिलाओं ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को बताया कि ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें गुमराह किया। कई लोग शर्मिंदगी के कारण अपने परिवार को अपने अनुभव के बारे में बताने से हिचकिचा रहे हैं। हवाई अड्डे पर निर्वासितों से मिलने वाले पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने प्रवासियों को उनके प्रियजनों से संपर्क करने में मदद की और उनके घर लौटने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस मामले पर चर्चा के लिए लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने गुरुवार को सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

एजेंटों ने अवैध मार्गों से विदेश भेजा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि प्रवासियों को बहुत दिनों बाद गर्म खाना मिला है। साथ ही, सरकार उन एजेंटों की जानकारी भी जुटा रही है जिन्होंने इन्हें अवैध तरीकों से विदेश भेजा। इनमें से कुछ लोग एक साल या उससे अधिक समय तक यूके में रहे और फिर अमेरिका चले गए।

बच्चों को छोड़कर सभी को हथकड़ी लगाई गई

अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार सभी लोगों को, बच्चों को छोड़कर, हथकड़ी लगाई गई थी। लैंडिंग के बाद अधिकांश लोग सामान्य दिखे, लेकिन कुछ मानसिक रूप से टूटे हुए थे। उन्हें दाल–चावल, रोटी और सब्जी सहित गर्म भोजन दिया गया, जबकि बच्चों को बिस्कुट, जूस और रंग भरने की किताबें दी गईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने वर्षों बाद गर्म, ताजा भोजन खाया है।

एजेंटों ने लिए 130 से 150 लाख रुपये

अधिकारी ने बताया कि कई प्रवासियों को ट्रैवल एजेंटों ने धोखा दिया, जिससे वे अपना नाम बताने में भी झिझक रहे थे। वे अपने दर्दनाक अनुभव साझा कर रहे हैं और कुछ ने अनुरोध किया कि उनके गांववालों को उनके निर्वासन की

जानकारी न दी जाए। निर्वासितों के रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने अमेरिका जाने के लिए 130 से 150 लाख रुपये खर्च किए, जहां वे अवैध रूप से पहुंचे और शरण के लिए आवेदन करने की उम्मीद कर रहे थे।

230 लाख रुपये देकर अमेरिका में बना बस ड्राइवर

अमृतसर पहुंचे एक युवक के दादा ने बताया कि उनका पोता 15 दिन पहले ही अमेरिका गया था, लेकिन वह इस फैसले के खिलाफ थे। परिवार को यह नहीं पता कि उसे भेजने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया। वहीं, एक अन्य व्यक्ति के रिश्तेदार ने बताया कि वह एक महीने पहले अमेरिका पहुंचा था और वहां 230 लाख रुपये खर्च कर बस चालक बन गया।

40 घंटे का सफर नरक जैसा

पंजाब के होशियारपुर के ताहली गांव के 40 वर्षीय हरविंदर सिंह भी उन 104 प्रवासियों में शामिल थे, जिन्हें अमेरिका ने वापस भेजा। उन्होंने बताया कि 40 घंटे तक उन्हें हथकड़ियों में रखा गया, पैरों में जंजीरें थीं और वे अपनी सीट से हिल भी नहीं सकते थे। बार-बार अनुरोध करने के बाद ही उन्हें खुद को घसीटकर शौचालय जाने की अनुमति

अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए ये भारतीय डौंकी रूट यानी गैर-कानूनी तरीकों से वहां पहुंचे थे। उन्हें एजेंटों के जरिए पनामा, मैक्सिको आदि के जंगलों के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करवाया गया था। इन एजेंटों की फीस प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपये तक होती है।

मिली। हरविंदर ने बताया कि यात्रा के दौरान वे ठीक से खाना नहीं खा पाए। उन्हें हथकड़ियों के साथ ही भोजन करने को कहा गया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों से हथकड़ी खोलने की विनती करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से कष्टदायक थी बल्कि मानसिक रूप से भी थका देने वाली थी। एक दयालु चालक दल के सदस्य ने उन्हें फल दिए। हरविंदर ने कहा कि वह सो नहीं सके क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से किया गया वादा याद आ रहा था। जून 2024 में, उन्होंने और उनकी पत्नी कुलजिंदर कौर ने अमेरिका जाने का फैसला किया। 13 साल से विवाहित इस दंपति ने अपनी एक एकड़ जमीन गिरवी रखकर और ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेकर 142 लाख रुपये जुटाए। लेकिन एजेंटों ने उन्हें आठ महीने तक एक देश से दूसरे देश घुमाया और अंततः अमेरिका पहुंचने से पहले ही निर्वासित कर दिया गया।

8 महीने तक एक देश से दूसरे देश

कुलजिंदर ने बताया कि उनके पति को लगातार अलग-अलग देशों में भेजा गया और वह कभी अमेरिका नहीं पहुंच सके। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन सब कुछ दस्तावेजों में दर्ज कर कुलजिंदर को वीडियो भेजते रहे। आखिरकार, उनके निर्वासन की खबर गांववालों से कुलजिंदर को मिली, जिससे वह सदमे में आ गईं।

संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका को अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का अधिकार है, लेकिन भारत सरकार को अमेरिका से इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सैन्य विमान में भेजने की जरूरत नहीं थी और न ही हथकड़ी लगाने की। ये लोग अपराधी नहीं हैं, बल्कि पीड़ित हैं, जिन्हें बेहतर भविष्य की तलाश में ठगा गया।

‘गोल्ड कार्ड’ खरीदो और अमेरिका की आजीवन नागरिकता पाओ

अमेरिका में बसने के लिए लेना होगा 50 लाख डॉलर की कीमत का ‘गोल्ड कार्ड’, ट्रंप अमीर विदेशी निवेशकों के माध्यम से करेंगे अमेरिका में नौकरियों का सृजन

डोनाल्ड ट्रंप की यह योजना पुराने ईबी–5 वीजा कार्यक्रम को समाप्त कर एक नया रूप देने की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिका में अमीर विदेशी निवेशकों के माध्यम से नौकरियों का सृजन कराना है।

आव्रजन पर ट्रंप की सख्ती

राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन नियमों को कड़ा कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि भारत सहित कई अन्य देशों के लोग अब अमेरिका जाने से पहले कई बार सोचने लगे हैं। लेकिन अब ट्रंप ने विदेशियों के लिए अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का एक नया ऑफर पेश किया है दृ गोल्ड कार्ड। इस कार्ड को खरीदने पर अमेरिकी नागरिकता मिल जाएगी, जिससे व्यक्ति बिना किसी रोक–टोक के अमेरिका में रह सकता है।

क्या है गोल्ड कार्ड

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा है कि वे ‘ईबी–5’ अप्रवासी निवेशक वीजा के नए संस्करण पर विचार कर रहे हैं। यह लोगों को अमेरिका में स्थायी निवास की अनुमति देगा और फिलहाल इसे गोल्ड कार्ड नाम दिया गया है, हालांकि अभी इसका आधिकारिक नाम तय नहीं हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक

- साल 2021 में 1,32,675 भारतीयों को अमेरिका में काम करने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस मिली थी।
- साल 2023 में यह संख्या बढ़कर 3,98,317 हो गई।
- साल 2024 में अमेरिका ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख वीजा जारी किए, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या भ्1-ठ वीजा धारकों की थी।
- ट्रंप की यह नई गोल्ड कार्ड योजना अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देखने वाले अमीर निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन यह तय कर रहा है कि यह गोल्ड कार्ड किन्हें दिया जाएगा। यह केवल उन अमीर बिजनेसमैन या निवेशकों को मिलेगा जो अमेरिका में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे यह गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं, ताकि अमीर निवेशक अमेरिका में आ सकें। इस कार्ड के धारकों को विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे। योजना की पूरी तैयारी के बाद अगले दो हफ्तों में इसकी विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। गोल्ड कार्ड की कीमत 50 लाख डॉलर (लगभग 44 करोड़ रुपये) तय की गई है। अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक लोगों को इस कार्ड को खरीदना होगा।

गौरतलब है कि विदेशी अमीर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ईबी–5 कार्यक्रम 1990 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य विदेशी निवेशकों के माध्यम से अमेरिका में रोजगार का सृजन और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना था।

हालांकि, अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक का कहना है कि पुराना ईबी–5 कार्यक्रम पूरी तरह से बकवास, दिखावटी और धोखाधड़ी से भरा था। यह सिर्फ कम कीमत पर ग्रीन कार्ड देने का एक तरीका बन गया था। इसी कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पुराने कार्यक्रम को खत्म कर गोल्ड कार्ड योजना लागू करने का फैसला किया है।

कितने भारतीय अमेरिका जाने का सपना देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विदेश में बसने के लिए भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका है। दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी अमेरिका में रहते हैं।

अमेरिका अपने नियम कानून से चलेगा, भारत को भी घुसपैठियों से ऐसे ही निपटना होगा

लोकसभा में विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है।

संजय सक्सेना, लखनऊ

संसद से सड़क तक विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट फिर से बदल लिया है। कल तक महाकुंभ में भगदड़ हादसे पर जमीन-आसमान एक किये विपक्षी नेताओं की जमात अब अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वहां से भारत भेजे जाने पर सियासत तलाशने लगा है। संसद के बजट सत्र में महाकुंभ हादसे को पीछे ढकेल कर विपक्ष अब लगातार अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन को मुद्दा बनाने लगे हैं।

संसद के बाहर हो-हल्ला तो बाहर धरना दिया जा रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान भारतीयों के डिपोर्ट का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कहते हैं कि अमेरिका सरकार के इस रवैये से बेहद दुखी हूं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे हैं लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 100 से ज्यादा भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजा है, वो पूरी तरह से अमानवीय है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। विपक्ष ट्रम्प और मोदी के रिश्तों को लेकर भी तंज कस रहे है। लगता नहीं है कि यह सियासत जल्दी थम जायेगी। क्योंकि अभी अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे करीब 150 और भारतीयों को भी अमेरिका

से निकाला जाना है। वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में वैध तरीके से रह रहे करीब सात लाख भारतीय बिना भेदभाव के वहां अपना जीवनयापन कर रहे हैं। एक तरफ सिसासतदारों का एक धड़ा अमेरिका के रवैये की आलोचना करके मोदी सरकार को घेर रहा है तो वहीं कुछ बुद्धिजीवी पूछ रहे हैं भारत सरकार, अमेरिका से सबक लेकर कब यहां यह रहे गैर भारतीयों को देश से निकालेगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में करीब पांच करोड़ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर तुष्टिकरण की सियासत के चलते कुछ राजनैतिक दलों के आकाओं द्वारा इन्हें उन्हें पाला पोसा जा रहा है। उनके आधार और पैन कार्ड बनवाये जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया जा रहा है। जबकि यह घुसपैठिये कई आपराधिक वारदातों में लिप्त मिल जाते हैं।

विपक्ष को इसलिये सियासत चमकाने का मौका मिल गया क्योंकि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट में भारत लाया गया था। हालांकि अमेरिका सरकार की ओर से इस तरह क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है। भारत सरकार की ओर से इस पूरे प्रकरण पर राज्यसभा में प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने संसद में कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल दर साल यह होता रहा है। इस तरह (यानी हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया) डिपोटेशन करने का तरीका नया नहीं है।

अमेरिका ने अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई की। खैर, सियासत के बीच एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद सभी भारतीयों को कस्टम व इमीग्रेशन चेकिंग

विपक्ष को इसलिये सियासत चमकाने का मौका मिल गया क्योंकि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट में भारत लाया गया था। हालांकि अमेरिका सरकार की ओर से इस तरह क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है।

के लिए भेज दिया गया। उक्त विभागों की ओर से सभी के दस्तावेजों और बैकग्राउंड की चेकिंग की जा रही है, ताकि पता चल सके कि जो भी अवैध तरीके से रह रहे थे, उनके खिलाफ भारत के किसी भी राज्य या शहर में कोई आपराधिक केस दर्ज है या नहीं। अगर किसी के खिलाफ इस तरह का कोई रिकार्ड पाया जाता है तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच चल रही है। अमेरिका से भारत लाए गए 104 भारतीयों में गुजरात के 33, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के तीन, उतर–प्रदेश एवं चंडीगढ़ के 2–2 लोग शामिल हैं। इनमें आठ से दस साल के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, अमेरिका सरकार की ओर से कुल 205 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी। बाकी के लोग कब आएंगे, फिलहाल इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, अमेरिका से भारत लौट रहे अवैध प्रवासियों की पहली फ्लाइट चर्चा में जरूर है, इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इस वापसी के पीछे भारत को एक और बड़ा फायदा होने वाला है। पंजाब पुलिस ने लगभग 100 कुख्यात अपराधियों की पूरी हिस्ट्री तैयार कर ली है, जिनमें से 20 के अमेरिका में छिपे होने की आशंका है। अब यह संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका से अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।

बता दें अमेरिका में भारत के कई मोस्ट वांटेड अपराधी छिपे हुए हैं। इनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई (गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई), पुलिस प्रतिष्ठानों पर ग्रेनेड हमलों में शामिल हैप्पी पासिया, ड्रग तस्कर सरवन भोला, और गोपी नवांशहरिया जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भी पंजाब में हिंसा फैलाने और अवैध प्रवास को बढ़ावा देने में शामिल हैं, ऐसे में उसके तैयार किए गए गुर्गे भी इस वापसी में शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की शुरुआत इस दिशा में भी मददगार साबित हो सकती है।

अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान सी–17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान ठीक 2 बजकर 15 मिनट पर अमृतसर एयरपोर्ट पर एविएशन क्लब की तरफ लैंड करवाया गया। इसमें 104 भारतीय सवार थे। सभी को हथकड़ी लगाकर अमेरिका सेना की देखरेख में भेजा गया है। इस विमान ने मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरी थी, जो कि करीब 35 घंटे की उड़ान भरकर अमृतसर पहुंचा। वहीं विमान पहुंचने से ठीक पहले भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकार भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह विभाग, भारतीय सेना सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

उधर, 05 फरवरी को अमेरिकी विमान के अमृतसर पहुंचने के बाद एविएशन क्लब में ही अमेरिका से आए अधिकारियों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग की गई। हालांकि मीटिंग किन मुद्दों पर रही, इस पर अभी किसी भी अधिकारी की ओर से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के अधिकारियों के समक्ष अवैध तौर पर आने वाले लोगों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा जो एजेंट लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का काम कर रहा है। उन पर भी कड़ी

यूपी की नई आबकारी नीति, एक तीर से कई निशाने

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश

नई आबकारी नीति में सबसे बड़ी बातों पर गौर किया जाये तो यह साफ है कि यूपी सरकार एक तो शराब कारोबार के धंधे में मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व को कम करना चाहती है। वहीं रंगीन पानी से सरकार अधिक से अधिक कमाई करने में भी गुरेज नहीं कर रही है। इसके अलावा योगी सरकार की नजर हरियाणा की आबकारी नीति में भी सेंधमारी की है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा नई आबकारी उत्पाद शुल्क नीति को मंजूरी दिये जाने के बाद शराब के धंधे को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई आबकारी नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नई आबकारी नीति में सबसे बड़ी बातों पर गौर किया जाये तो यह साफ है कि यूपी सरकार एक तो शराब कारोबार के धंधे में मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व को कम करना चाहती है। वहीं रंगीन पानी से सरकार अधिक से अधिक कमाई करने में भी गुरेज नहीं कर रही है। इसके अलावा योगी सरकार की नजर हरियाणा की आबकारी नीति में भी सेंधमारी की है।

दरअसल, दिल्ली और एनसीआर के शराब के शौकीन लोग सस्ती शराब के चक्कर में गुड़गांव पहुंच जाते हैं। इसमें नोयडा और गाजियाबाद में रहने वाले पियक्कड़ भी शामिल हैं,जिसके चलते यूपी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। गुड़गांव में सस्ती शराब होने के चलते ही दिल्ली से सटे यूपी के जिलों की शराब की दुकानों में सन्नाटा पसरा रहता है।

योगी सरकार की नई शराब नीति के बदलावों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में अब कंपोजिट शराब की दुकानें देखने को मिलेंगी। बीयर और विदेशी शराब की दुकानों को एक ही इकाई में विलय करा जा सकेगा। साथ ही राज्य में अंगूर के बागानों और माइक्रोब्रेवरीज की शुरुआत के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी की नई आबकारी नीति से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को फायदा होगा। शहर की 2021–22 की आबकारी नीति अगस्त 2022 में वापस लिए जाने के बाद से दिल्ली में शराब की दुकानों को दो साल तक विकल्प और स्टॉक का संकट झेलना पड़ा था। नई शराब नीति का मुख्य उद्देश्य 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना और शराब कारोबार को अधिक मजबूत बनाना है. योगी सरकार 6 साल बाद नई शराब नीति लेकर आई है, हालांकि, यह अभी तय नहीं किया गया है कि शराब के दामों में कोई बदलाव होगा या नहीं। इस नीति को लागू करने में पहले देरी हुई थी क्योंकि महाकुंभ 2025 और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी।

नई आबकारी नीति को 05 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई तो यह कहा जाने लगा अब तक, दिल्ली के ग्राहक गुरुग्राम से शराब खरीदने को मजबूर थे। गुरुग्राम में शराब सस्ती और इसके अधिक विकल्प मिल रहे थे। यूपी की नई उत्पाद शुल्क नीति के साथ राज्य में अधिक विकल्प मिलेंगे

और पूर्वी और उत्तरी दिल्ली के लोगों को गाजियाबाद–नोएडा से शराब लेना पास रहेगा। आबकारी नीति में नई सुविधाओं की घोषणा पर यूपी के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह कहते हैं कि राज्य में अब तीन प्रकार की शराब की दुकानें होंगी. मॉडल शॉप, देशी शराब की दुकानें और कंपोजिट दुकानें। उत्तर प्रदेश में अब हर जिले में फलों से तैयार वाइन की एक–एक दुकान होगी।

मंडल मुख्यालय में इसके लिए लाइसेंस फीस 50 हजार रुपये व अन्य जिलों में 30 हजार रुपये फीस होगी। इससे फल उत्पादकों के उत्पादों की खपत बढ़ेगी। इसके अलावा हर राज्य में बड़े परिसर वाली कंजिट दुकानें खुलेंगी। यहां एक साथ विदेशी मदिरा, वाइन व बीयर उपलब्ध होगी लेकिन यहां मदिरापान की अनुमति नहीं होगी। विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर में शीशे की बोतल व सिरोंग पैक में भी उपलब्ध होगी।

नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या फर्म को अधिकतम दो दुकानें आवंटित हो सकेंगी। यह बात सामने आते ही सत्तर से नब्बे तक के दशक की याद ताजा हो जाती है. साल 1970–80 तक लाला मणिलाल, राजा राम जायसवाल, दीप नारायण जायसवाल, लाला राम प्रकाश जायसवाल, श्री नारायण साहू का बोलबाला था। 1980–90 तक लाला जगन्नाथ जी, लाला मणिलाल, विनायक बाबू थे। 1985–88 के बाद जवाहर लाल और गोरखपुर के बद्री बाबू जायसवाल आए. उत्तर प्रदेश के शराब व्यापार पर आठ या नौ व्यापारियों जैसे बाबू किशनलाल, बद्री प्रसाद जायसवाल आदि का सिक्का चलता था. लेकिन सबसे बड़ा नाम था जवाहर जायसवाल का. वो लिकर किंग के नाम से जाने जाते थे. इन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, यानि आसान भाषा में चंद लोगों का एक शक्तिशाली गुट, जिसके सामने सरकार भी झुक जाती थी।

साल 1999 से 2004 तक सांसद रहे जवाहर जायसवाल अक्सर दावा करते मिल जाते थे कि वर्ष 1993 से लेकर 2000 तक मेरे ग्रुप के पास 22 जिले थे. इतना बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान में कभी किसी के पास नहीं रहा. नब्बे के दशक में अपने रसूख के चरम पर राज्य में सरकारी नीतियों, शराब के दाम, व्यवस्था पर दखल रखने वाले जवाहर जायसवाल के पास, उनके मुताबिक, करीब 10,000 दुकानें थीं. वैसे अकेले जवाहर जायसवाल की बात नहीं हैं यूपी में लम्बे समय से शराब के व्यापार पर जायसवालों का कब्जा रहा है।

जवाहर जायसवाल को ये बिजनेस विरासत में मिला. वो 1972 में बिजनेस में आए और अगले आठ सालों में पूरे बनारस पर उनका एकाधिकार सा हो गया. जायसवाल समाज से जुड़े कुछ लोग कहते हैं कि 50 साल पहले तक हमें कलाल बोला जाता था. कलाल मतलब जो कलाली का बिजनेस करता है. कलाली मतलब शराब. कलाल को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था. लोग हमारा छुआ पानी भी नहीं पीते थे. लेकिन वक्त बदला और शराब के बिजनेस पर जायसवाल समुदाय का एकाधिकार ऐसा हुआ कि उनके प्रति समाज के अन्य वर्ग के लोगों का एकदम नजरिया ही बदल गया।

खैर, 1993 से 2001 तक जवाहर जायसवाल का दबदबा रहा. वो लिकर किंग के नाम से जाने जाते थे. लेकिन समय के साथ आबकारी नीति में कई उतार–चढ़ाव देखने को मिले।

साल 2000 में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी. एक्साइज मंत्री थे सूर्य प्रताप शाही. शराब व्यापारियों की मनमानी खत्म करने के लिए साल 2001–02 में नई आबकारी नीति आई और शराब कारोबार के बड़े प्लेयर के रूप में पॉटी चड्ढा का उदय हुआ और साल 2012 तक उनका वर्चस्व रहा. मायावती और अखिलेश यादव सरकारों से नजदीकियों के आरोपों के बीच पॉटी चड्ढा का साम्राज्य फैलता गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी एक्साइज और 2001 की आबकारी नीति पर पीएचडी कर चुके डॉक्टर एसपी गौड़ के मुताबिक 2001 की आबकारी नीति में मानवीय लॉटरी से दुकानों के आवंटन का प्रावधान था और दुकाने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपनी या किराए पर प्रॉपर्टी हो वो भी आवेदन कर सकता था. इसके अलावा रिटेल दुकानदार कहीं से भी शराब खरीद सकते थे. इस नीति के अंतर्गत हर बॉटल पर होलोग्राम लगाया गया था ताकि उसकी बिक्री राज्य के भीतर हो।

प्रवीर कुमार के मुताबिक इस नीति में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि नीलामी से मिलने वाली राशि की जगह मिलने वाली आमदनी को दो भाग में विभाजित कर दिया गया, लाइसेंस फीस और ड्यूटी. एक दुकान की लाइसेंस फीस वहां होने वाली बिक्री के आधार पर निर्धारित की गई, जबकि फैसला हुआ कि शराब पर लगने वाला कर उसके डिस्टिलरी से बाहर निकलने से पहले ही सरकार इकट्ठा कर लेगी. नतीजा ये हुआ कि पुराने बड़े नाम धीरे धीरे बिजनेस से बाहर हो गए, मोनोपली राज पर रोक लगी और नए लोग जैसे पूर्व बैंक अधिकारी, रिटायर्ड लोग, एमबीए ग्रैजुएट बाजार में उतरे जो पहले इसकी धूमिल छवि की वजह से इससे आमतौर पर दूर रहते थे. यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है।

अखिलेश पर भारी पड़ रहा है महाकुंभ का विरोध

सपा की हालात यह हो गई है कि मोदी-योगी सरकार के हर फैसले में अखिलेश को साम्प्रदायिकता और खामियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। धर्म की बात की जाये तो अखिलेश महाकुंभ में खामियां तलाश रहे हैं। हाल यह है कि महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर जहां बच्चा-बच्चा योगी की तारीफ कर रहा है।

अजय कुमार, लखनऊ

समाजवादी पार्टी आजकल दुविधा की सियासत से जूझ रही है। उसके एक तरफ कुआँ तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। इसी कारण समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की सियासत तो खुलकर कर रही है, लेकिन हिन्दूवादी राजनीति को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं। सपा की हालात यह हो गई है कि मोदी–योगी सरकार के हर फैसले में अखिलेश को साम्प्रदायिकता और खामियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। धर्म की बात की जाये तो अखिलेश महाकुंभ में खामियां तलाश रहे हैं। हाल यह है कि महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर जहां बच्चा–बच्चा योगी की तारीफ कर रहा है। वहीं अखिलेश और उनकी टीम मौनी अमवस्या के शाही स्नान के समय मची भगदड़ में हुई तीस लोगों की मौत पर राजनीति करने से उबर नहीं पा रही है, जिस समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार ने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर अंधाधुंध

गोलियां बरसा कर उन्हें मौत के घाट पर सुला दिया था, इसमें कितने लोग मरे थे यह आज भी रहस्य बना हुआ है। खास बात यह है कि योगी सरकार कह रही है कि भगदड़ में तीस लोग मरे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी नेता इसे झूठ बता रहे है।

सपा नेता तर्क दे रहे हैं हजारों जूते–चप्पलें और बैग घटना स्थल पर पड़े मिले थे, जिससे साबित होता है कि हजारों लोग मरे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि यदि समाजवादी पार्टी के प्रमुख सहित अन्य तमाम नेताओं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदि की यह बात मान भी ली जाये कि भगदड़ में हजारों लोग मरें हैं तो वह पीड़ित लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं जिनके परिवार के लोग भगदड़ में मारे गये हैं। यही बात बताती है कि विपक्ष भगदड़ के नाम पर महाकुंभ और योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। इसीलिये अखिलेश का साथ दलित और पिछड़े लोग भी छोड़ने लगे हैं। अखिलेश सिर्फ मुस्लिमों के नेता बनकर रह गये हैं, उसमें भी उदारवादी और पढ़े लिखे मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं।

वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव शुरू से ही महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। यह बात विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि पहले दिन से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफवाह फैलाने में लगे हैं। अखिलेश सबसे पहले कहते हैं कि महाकुंभ को इतना पैसा और विस्तार देने की क्या जरूरत थी। फिर कहते हैं कि 65–70 के लोग महाकुंभ में स्नान नहीं कर पा रहे हैं। फिर कहते हैं महाकुंभ जैसा कोई

शब्द ही नहीं है। सरकारी पैसा निकालने के लिये महाकुंभ शब्द रचा गया। अखिलेश तंज कसते हैं कि 50 नहीं 60 करोड़ लोग आ चुके हैं। इसी तरह से लालू यादव महाकुंभ को फालतू बताते हैं तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं, लेकिन कोई इसका विरोध नहीं करता है। इसी तरह से सोशल मीडिया पर इधर–उधर की फोटो और वीडियो को महाकुंभ की घटना बता कर प्रचारित किया जा रहा है।

गौरतलब हो, आज महाकुंभ पर हो हल्ला मचाने वाले समाजवादी इससे पूर्व अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के समय भी ऐसा करते नजर आये थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो मंदिर निर्माण के उदघाटन अवसर पर भी मौजूद नहीं रहे थे। कारण बहुत साफ था वहीं चुनाव के समय उन्हें ईवीएम और चुनाव आयोग में खामियां नजर आती हैं। योगी जब अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो समाजवादी उर्दू को आगे बढ़ाने का राग अलापने लगते हैं।

समाजवादी पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि यूपी में जिस भारतीय जनता पार्टी को सपा के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी अखाड़े में कभी उभरने नहीं दिया, उसी भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव की गैर जिम्मेदाराना और अपरिपक्त राजनीति ने अपनी सियासत चमकाने का पूरा मौका दिया। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के नेतृत्व में 2012 में अंतिम बार चुनाव जीती थी और अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से आज तक अखिलेश अपने बल पर कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाये हैं। 2024 के आम चुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन अखिलेश कांग्रेस की बैसाखी के सहारे यह सफलता हासिल कर पाये थे। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस का साथ लेकर सपा उन सीटों पर भी जीत नहीं हासिल कर पा रही है जिसे कभी समाजवादी पार्टी की परम्परागत सीट माना जाता था। पहले विधान सभा चुनाव के समय मुरादाबाद की कुंदरकी और हाल ही में अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर सपा को मिली हार से यह साबित हो गया है कि अखिलेश यादव अपना जनाधार नहीं बचा पा रहे हैं। यह और बात है कि अखिलेश दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताने का दंभ जरूर भरते हैं। यही अखिलेश और समाजवादी पार्टी की नियति बन गई है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव अपने ही बुने

1984 के सिख विरोधी दंगो के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद

सज्जन कुमार पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से इसी दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा पा चुके हैं। ऐसे में अब निचली अदालत द्वारा एक और मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सिख दंगों में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है।

कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से इसी दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा पा चुके हैं। ऐसे में अब निचली अदालत द्वारा एक और मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सिख दंगों में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है।

क्या था 1984 का सिख विरोधी दंगा

1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे।

- **जून 1984:** स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने वाले आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मार गिराया था। इस अभियान में भिंडरावाले और उसके कई समर्थकों की मौत हुई थी। इस ऑपरेशन की मंजूरी स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल, स्वर्ण मंदिर में इस सैन्य कार्रवाई से कई लोगों की भावनाएं आहत हुई थीं।
- **31 अक्टूबर 1984:** ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें करीब 3,000 से 5,000 लोगों की जान गई। अकेले दिल्ली में ही लगभग 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

अब इस घटना के लगभग 41 साल बाद, सज्जन कुमार को एक और मामले में सजा मिली है। वहीं, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर भी मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के एचकेएल भगत और कमलनाथ भी सिख दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी रह चुके हैं।

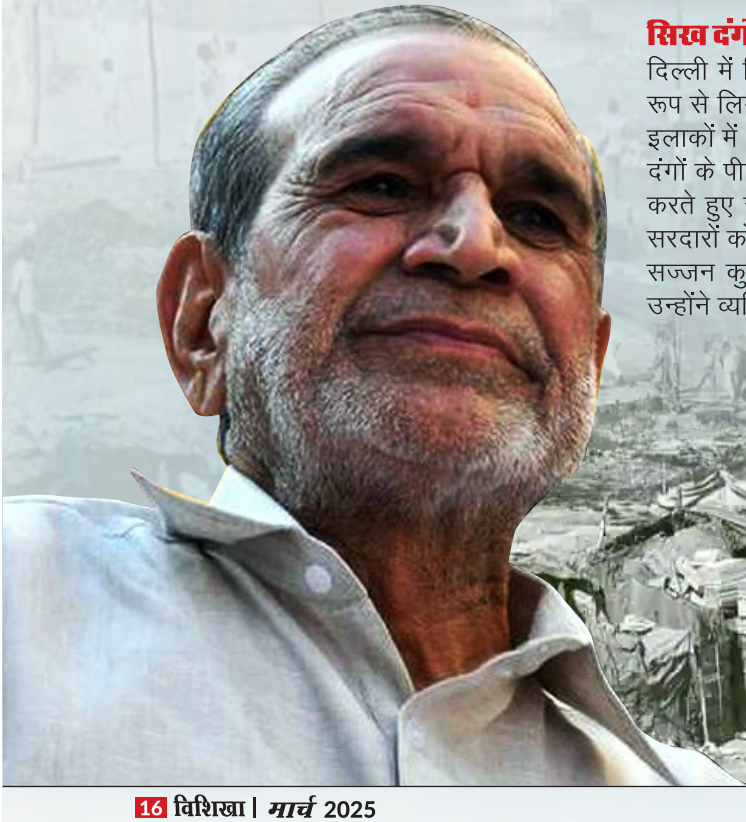

सिख दंगों में सज्जन कुमार की भूमिका

दिल्ली में सिख विरोधी दंगों को भड़काने में सज्जन कुमार का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, खासकर सुल्तानपुरी, कैंट और पालम कॉलोनी जैसे इलाकों में।

दंगों के पीड़ितों के अनुसार, 1 नवंबर 1984 को दिल्ली में भीड़ को संबोधित करते हुए सज्जन कुमार ने कथित तौर पर कहा थाकृ ष्हमारी मां मार दी, सरदारों को मार दो।

सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामलों में कई गवाहों ने बयान दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिखों के घरों की पहचान करवाई और भीड़ को

हमले के लिए उकसाया। आरोप यह भी था कि उनके समर्थकों ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के जरिए सिखों के घर और व्यवसाय चिह्नित किए, फिर उन पर हमले किए और आगजनी की। कई सिखों को उनके घरों से निकालकर बेरहमी से मारा गया।

जानिए सज्जन कुमार का नाम किन घटनाओं से जुड़ा था

- **31 अक्टूबर 1984 दंगा:** इस दौरान उन्होंने दिल्ली कैंट इलाके में भीड़ को उकसाया, जिससे कई घरों में आगजनी हुई। सज्जन कुमार के उकसावे के बाद दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में भीड़ ने केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंद्र सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या कर दी।
- **सुल्तानपुरी दंगे:** पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की जांच रिपोर्ट के अनुसार, सुल्तानपुरी इलाके में दंगों के पीड़ितों ने कांग्रेस सांसद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया था। बाद में कई लोगों ने इस सांसद की पहचान सज्जन कुमार के रूप में की।

अदालत द्वारा सजा मिलने के बाद सिख दंगों में उनकी भूमिका पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है।

जानिए किस-किस मामले में दोषी पाए गए सज्जन कुमार

- सज्जन कुमार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण तथ्य और सबूत मौजूद होने के बावजूद, उनके खिलाफ किसी भी मामले में आरोप तय नहीं हो सके। 2002 में सिख दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
- 2005 में, सीबीआई ने जीटी नानावटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ नया मामला दर्ज किया।
- 2010 में, इस मामले की सुनवाई दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में हुई। इस मामले में बलवान खोखर, महेंद्र यादव, महा सिंह समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया।
- 2013 में, अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। हालांकि, इस मामले में पांच अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष में भारी आक्रोश था। एक प्रदर्शनकारी ने तो सुनवाई कर रहे जज की ओर जूता तक उछाल दिया था।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को तब संज्ञान में लिया, जब एक पीड़िता और गवाह, जगदीश कौर ने सीबीआई के साथ मिलकर सज्जन कुमार के खिलाफ केस दायर किया। उन पर पांच सिखों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। जिन सिखों की हत्या हुई थी, उनमें जगदीश कौर के पति और बेटे के साथ–साथ जगशेर सिंह के तीन भाई भी शामिल थे। इस मामले में एक अन्य प्रमुख गवाह निरप्रीत कौर थीं।
- सीबीआई ने हाईकोर्ट में बताया था कि इन घटनाओं के चश्मदीद गवाहों ने सज्जन कुमार का नाम जांच आयोग के सामने लिया था और नरसंहार में उनके खिलाफ जांच की मांग की थी। हालांकि, निचली अदालत ने चश्मदीदों की गवाही देने से रोक दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान, एक अन्य चश्मदीद गवाह, चम कौर ने अदालत में बताया था कि उन्होंने सज्जन कुमार को सुल्तानपुरी इलाके में भीड़ को संबोधित करते हुए देखा था।

जानिए किस मामले में हुई सज्जन कुमार को उम्रकैद

सज्जन कुमार को अब 1984 के सिख दंगों से जुड़े एक और मामले में दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में भीड़ को भड़काने से संबंधित है, जिसमें जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया, जिससे बड़े पैमाने पर सिखों के घरों और दुकानों में लूटपाट और आगजनी हुई। इसी दौरान, एक घर में लूटपाट और आग लगाने से पहले भीड़ ने दो सिखों को जिंदा जलाकर मार दिया था।

जांच कर रही तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सज्जन कुमार के खिलाफ जसवंत सिंह की पत्नी को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया। हालांकि, सज्जन कुमार के वकीलों ने उनकी गवाही को खारिज करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि जसवंत सिंह की पत्नी घटना के सात साल बाद गवाह के रूप में सामने आईं, इसलिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि इस मामले में पहली एफआईआर घटना के सात साल बाद, 1991 में दर्ज की गई थी। यह एफआईआर 9 सितंबर 1985 को दिए गए एक शपथ पत्र (एफिडेविट) के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसे शिकायतकर्ता ने जस्टिस रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले आयोग को सौंपा था। 2014 में, मोदी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच तेज की और पुराने मामलों को दोबारा खंगालना शुरू किया।

भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार आईआईटी मद्रास कर रहा है निर्माण

आईआईटी मद्रास ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक तैयार किया है। इस ट्रैक की मदद से 350 किलोमीटर की दूरी केवल 30 मिनट में तय की जा सकेगी। इसका अर्थ यह है कि यदि यह तकनीक साकार होती है, तो दिल्ली से जयपुर की लगभग 300 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर यह खबर साझा करते हुए लिखा, "सरकार के सहयोग से परिवहन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है।"

आईआईटी मद्रास कर रहा निर्माण

रेल मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित इस परियोजना का निर्माण आईआईटी मद्रास परिसर में किया गया है। उत्साहित अश्विनी वैष्णव ने कहा, "422 मीटर का यह पहला ट्रैक पॉड टेक्नोलॉजी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब समय आ गया है कि पहले दो मिलियन डॉलर के अनुदानों के बाद, तीसरा मिलियन डॉलर अनुदान भी आईआईटी मद्रास को हाइपरलूप परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाए।" रेलवे जल्द ही पहली वाणिज्यिक परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है।

'पांचवें परिवहन मोड' के रूप में जाना जाने वाला हाइपरलूप एक हाई–स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे लंबी दूरी की यात्रा को तेज और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विशेष कैप्सूल के माध्यम से निर्वात ट्यूबों में संचालित होता है, जिससे ट्रेनों की गति अत्यधिक तेज हो जाती है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "हाइपरलूप एक निर्वात ट्यूब में विद्युत चुंबकीय रूप से उत्तोलित (मैग्नेटिक लीविटेशन) पॉड का उपयोग करता है, जिससे घर्षण और वायु प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और पॉड को मैक 1.0 तक की गति तक पहुंचने की अनुमति मिलती है।" समुद्र तल पर मैक 1.0 की गति लगभग 761 मील प्रति घंटा होती है।

हाइपरलूप की विशेषताएँ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हाइपरलूप की मुख्य विशेषता यह होगी कि यह किसी भी मौसम की स्थिति से अप्रभावित रहेगा। इसमें दुर्घटनाओं की संभावना नहीं होगी। यह विमान की गति से भी दोगुनी तेज चलेगा, इसमें बिजली की खपत कम होगी और 24 घंटे परिचालन के लिए ऊर्जा भंडारण की सुविधा होगी।

यूपी में 'सस्ती' शराब से पीने वालों की होली

अजय कुमार, लखनऊ

यूपी में अंग्रेजी शराब के ठेके नए सिरे से होने हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. ऐसे में जिन दुकानदारों के पास ज्यादा स्टॉक है, वो रियायती दरों पर शराब बेचकर अपना स्टॉक क्लियर करने की कोशिशों में लगे हैं. ताकि कोटे की बची शराब से कुछ और कमाई हो जाये। यही वजह थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में अंग्रेजी शराब की एक दुकान पर जैसे ही दुकानदार ने शराब के रेटों में भारी छूट का बोर्ड लगाया तो देखते ही देखते वहां भीड़ उमड़ पड़ी. लोग पूरी की पूरी पेटियां खरीदकर ले जाने लगे, हालात ऐसे बन गए कि शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई और लोग शराब खरीद कर ले जाते मिले. जल्द ही यह नजारा अन्य जिलो में भी देखने को मिल सकता है, जिससे होली के रंग अंग्रेजी के साथ और चटक हो सकते हैं।

बहरहाल, आज भले ही कुछ जगह सस्ती शराब मिल रही हो, लेकिन एक अप्रैल से यूपी में शराब और बीयर पीने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है. इन्हें अब अपनी जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी. उत्तर प्रदेश में पहली अप्रैल से शराब और बीयर महंगी हो जाएगी. प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस और आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की वजह से

बता दें कि हाल ही में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई है. अब पुराने कोटेदारों की दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, बल्कि फिर से लॉटरी के द्वारा शराब की दुकानों की नीलामी होगी।

ऐसा होगा. नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर सभी लाइसेंसी फुटकर दुकानों पर बीयर और देसी तथा अंग्रेजी शराब के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी. नई दरें एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएंगी.

नये दामों की बात की जाये तो पहली अप्रैल से यूपी में बीयर के केन में औसतन 10 रुपये प्रति केन और बोतल पर 20 रुपये प्रति बोतल की मूल्य वृद्धि होगी. एक प्रमुख कंपनी ने तो मार्च के इन अंतिम दिनों में ही अपने दाम बढ़ा दिए हैं. कुछ और अच्छे ब्राण्ड की बीयर के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं. इसी तरह देसी शराब का 42.8 डिग्री तीव्रता का पउआ पहली अप्रैल से 75 रुपये के बजाए 90 रुपये का होगा. 36 डिग्री तीव्रता का देसी शराब का पउवा 65 रुपये के बजाए 70 रुपये का बिकेगा. अंग्रेजी शराब के पापुलर ब्राण्ड के क्वार्टर, अद्धे व बोतल के दामों में भी बढ़ोतरी होगी. अंग्रेजी शराब के क्वार्टर में 15 से 25 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की जाएगी.

बता दें कि हाल ही में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति 2025–26 को मंजूरी दी गई है. अब पुराने कोटेदारों की दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, बल्कि फिर से लॉटरी के द्वारा शराब की दुकानों की नीलामी होगी। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति के जरिए 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. नई आबकारी नीति के तहत मॉल्स, मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें को इजाजत नहीं दी जाएगी. वहीं अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानें लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी और कंपोजिट दुकानों को भी लाइसेंस जारी किया जाएगा. जिसमें देशी, विदेशी, बीयर और वाइन एक जगह पर मिल सकेगी. इस बार सरकार ने बियर और शराब का कोटा भी पांच से 10 फीसदी बढ़ाया है। इस बार शासन ने देसी मदिरा की दुकानों का कोटा 10 फीसदी बढ़ा दिया है। वहीं, बीयर की दुकान का पांच फीसदी और विदेशी मदिरा की दुकान का पांच फीसदी लाइसेंस शुल्क बढ़ाया गया है। विभाग की ओर से कंपोजिट दुकानें संचालित करने के लिए तैयारियां की जा रही है।

योगी ने किया महाकुंभ का समापन, सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया

अजय कुमार, लखनऊ

संगम तीरे चले 45 दिनों के महाकुंभ के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचें। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। आज उनके द्वारा यहां महाकुंभ के भव्य आयोजन का विधिवत समापन की घोषणा की गई। महाकुंभ के भव्य आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी। फिलहाल समापन के बाद भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस आयोजन का औपचारिक समापन करने महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने संगम घाट पर पूजा की। साथ ही गंगा मैया की आरती की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन को सफल बताते हुए। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि इस महा आयोजन ने सकल विश्व को 'सभी जन एक हैं' का अमृत संदेश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है कि एकता, समता, समरसता का महायज्ञ महाकुम्भ–2025, प्रयागराज भव्यता–दिव्यता के साथ सुरक्षा–स्वच्छता–सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर आज संपन्न हो गया है। विगत 45 पुण्य दिवसों में पूज्य साधु–संतों समेत 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर कृतार्थ हुए हैं। सकल विश्व को 'सभी जन एक हैं' का अमृत संदेश देने वाला यह मानवता का महोत्सव 'वसुधैव कुटुंबकम' के पुण्य भाव के साथ संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में पिरो रहा है। आपका मार्गदर्शन एवं शुभेच्छाएं हम सभी को सदैव नई ऊर्जा प्रदान करती हैं, हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी! हर हर–गंगे, भगवान बेनी माधव की जय!

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अरैल घाट पर मेला क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। महाकुंभ समापन पर सफाई अभियान चल रहा है। वहीं साथ में मौजूद ब्रजेश पाठक ने कहा कि महाशिवरात्रि के स्नान के बाद मैं महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। व्यवस्था से जुड़े हमारे सफाई कर्मी, अन्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, नर्सों और सभी का आभार प्रकट करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रतिबद्ध स्वच्छता दूतों की सतत सेवा से स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ–2025 प्रयागराज की परिकल्पना सिद्ध हुई है। आज प्रयागराज के अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान में अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ सहभाग किया। महाकुंभ–2025, प्रयागराज के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन!श्श्इस दौरान संगम क्षेत्र में सफाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपड़ा उठाया। वहीं उसे थैले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डाला। वहीं आज यानी कि गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे हैं। उन्होंने इस दौरान रेल अधकिारियों से मुलाकात की। बताया कि महाकुंभ के दौरान 16000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हुआ। बता दें कि महाशिवरात्रि पर हुए शाही स्नान के बाद महाकुंभ के समापन की औपचारिक घोषणा हो गई है। हालांकि अभी मेला परिसर को पूरा खाली होने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई।

महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान

देश की आधी से अधिक आबादी ने लगाई डुबकी

तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्म के करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यदि देश की कुल जनसंख्या से इसकी तुलना की जाए, तो लगभग 50 प्रतिशत भारतीयों ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई है।

13 जनवरी से शुरू हुए इस भव्य, दिव्य और सांस्कृतिक समागम ने महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर इतिहास रच दिया, जब श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ के पार पहुंच गई। जिससे यह महाकुंभ अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया।

इतनी बड़ी संख्या में किसी भी आयोजन में पहले कभी लोग नहीं जुटे थे। महाकुंभ में 45 दिनों के भीतर एक अस्थायी शहर में जितने श्रद्धालु आए, वह कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। 65 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अनुपम मिसाल पेश की है।

भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हों। यदि इसे विभिन्न देशों की जनसंख्या से तुलना करें, तो यह अमेरिका की दोगुनी, पाकिस्तान की ढाई गुना और रूस की चार गुना से अधिक आबादी के बराबर है। जापान की पांच गुना, यूके की दस गुना और फ्रांस की पंद्रह गुना आबादी के बराबर श्रद्धालुओं ने यहां संगम में पवित्र स्नान किया है।

सनातन धर्मावलंबियों की बात करें, तो देश के 60 प्रतिशत से अधिक और विश्व के लगभग 55 प्रतिशत श्रद्धालु इस पावन

स्नान का हिस्सा बन चुके हैं। इस आयोजन में 73 देशों के राजनयिकों के साथ भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक सहित अनेक देशों के अतिथि भी अमृत स्नान के लिए पहुंचे। नेपाल से भी 50 लाख से अधिक लोग महाकुंभ के साक्षी बने।

महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदों को भी पार कर गई। उन्होंने पहले 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन 11 फरवरी तक यह संख्या पार हो गई, और 22 फरवरी को 60 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। महाशिवरात्रि के दिन 65 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर महाकुंभ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

दिल्ली-राजस्थान से लेकर यूपी तक की विधान सभाओं में हंगामा

अजय कुमार, लखनऊ

यह अफसोसजनक है कि लोकसभा और राज्यसभा की तरह तमाम राज्यों की विधानसभाएं भी सत्ता और विपक्ष के जोर आजमाइश का अड्डा बनते जा रहे है, जिस कारण से जनहित के कई फैसलों पर निर्णय नहीं हो पाता है। हाल यह है कि राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी सरकार के खिलाफ इस लिये सड़क पर उतरी हुई है क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कह दिया। इसी प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता रेखा गुप्ता की चार दिन पुरानी सरकार को इसलिये घेर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं को ढाई हजार रूपये देने वाले वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता इस लिये विधान सभा नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने विधान सभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कह दिया था कि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, उन्हें फांसी पर तो नहीं लटका दिया जायेगा। बृजेश पाठक ने किसी नेता का नाम नहीं लिया,लेकिन क्योंकि यह बात कभी सपा के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक जनसभा के महिलाओं के बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर अपने विचार रखने के दौरान कही थी। इसलिये समाजवादी आग बबूला हो गये। विधान सभा में हंगामा खड़ा कर दिया कि नेताजी को अपमान बर्दाशत नहीं करेंगे। विधानसभा

अध्यक्ष सतीश महाना लगातार समाजवादी नेताओं से पूछ रहे हैं कि बताएं नेताजी का क्या अपमान किया गया है। यदि उनकी बात सही होगी तो वह मंत्री जी से माफी मंगवायेंगे,लेकिन समाजवादियों को हंगामे के अलावा कुछ रास नहीं आ रहा है।

बता दें उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2025 चल रहा है। आज 24 फरवरी को बजट सत्र के दौरान मुलायम सिंह के नाम पर हंगामा हो गया। दरअसल, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्न पहर में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मुलायम सिंह की कही गई बात पर तंज कसते हुए कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है इस बात को कितने सपा सदस्य मानते हैं। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर सपा सदस्यों ने वेल में आकर धरना दिया। सपा सदस्य नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सपा सदस्यों को बार-बार चेतावनी देते रहे पर सपाइयों का हंगामा जारी रहा।

दरअसल, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बयान पर सपा सदस्यों से पूछा था कि क्या उनकी बातों पर अमल करेंगे। नारेबाजी कर सपा सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर अमर्यादित टिप्पणी की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ब्रजेश पाठक पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सपा सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सपा विधायक सदन वेल में धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले शुक्रवार 21 फरवरी को प्रश्न प्रहर में सपा की सदस्य डॉ. रागिनी और माता प्रसाद के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी सपा पर खूब बरसे थे। सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपका बयान आपके नेता जैसा है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों को कि जिस तरह इनके नेता कहते हैं कि भारत विकसित देश नहीं बन सकता, वैसे ही यह भी दुर्भावनावश ऐसा कह रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सही लग रहा है कि सपाई जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश वर्ष 2029 तक वन ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हर हाल में हासिल कर लेगा। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को दस सेक्टर में बांट कर सभी को जिम्मेदारी सौंपी है। हर पंद्रह दिन में विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव इसकी समीक्षा करते हैं।

यूपीः आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनेंगे होटल, थीम पार्क और रिजॉर्ट

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अब सरकार नई सुविधाओं का विकास करेगी। इस एक्सप्रेसवे पर होटल, थीम पार्क, रिसॉर्ट और ऑटोमोबाइल शोरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

योगी सरकार ने बजट 2025–26 में न केवल नए एक्सप्रेसवे बल्कि पुराने एक्सप्रेसवे के उन्नयन पर भी ध्यान दिया है। यूपी में पहले से निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसलिए, भारी ट्रैफिक वाले आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को नए सिरे से और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ई–हब विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। हर ई–हब में होटल, फूड कोर्ट, थीम पार्क, रिजॉर्ट, वेयरहाउस, बैंक्वेट हॉल, ऑटोमोबाइल शोरूम और ट्रक यूजर जोन जैसी विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे भविष्य में यात्रियों के लिए इन एक्सप्रेसवे पर सफर और अधिक सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा।

योगी सरकार ने आगरा से लखनऊ तक 301 किमी लंबे एक्सप्रेसवे को और उन्नत बनाने की योजना बनाई है। पहले इस एक्सप्रेसवे की छोटी–छोटी खामियों को दूर किया जाएगा और साथ ही नई सड़क का भी निर्माण होगा। इसके लिए यूपीडा ने एक बड़ी योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त, आगरा एक्सप्रेसवे पर एक नया एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की भी तैयारी की जा रही है। फिलहाल, इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने इस परियोजना के लिए 12 स्थानों को चिन्हित किया है, जिनमें से 4 स्थान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर और 8 स्थान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब निर्माण और अन्य सुविधाओं पर 144 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 72 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे

जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेसवे के रूप में एक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। अप्रैल तक जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। सरकार की योजना इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जेवर को सीधे प्रयागराज और वाराणसी से जोड़ने की है, जिससे यात्रा अधिक तेज और सुविधाजनक हो सकेगी।

अगले 20 सालों में 80 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं कैंसर से मौत के मामले

डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में कैंसर के लगभग दो करोड़ नए मामले सामने आए, जबकि करीब 97 लाख लोगों की मृत्यु हुई।

कैंसर के मामले दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे हैं। वयस्कों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी इस गंभीर और जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कैंसर के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में कैंसर के लगभग दो करोड़ नए मामले सामने आए, जबकि करीब 97 लाख लोगों की मृत्यु हुई। फेफड़े, स्तन, कोलोरेक्टल, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर के मामले सबसे आम पाए गए। कैंसर के निदान के बाद अगले 5 वर्षों तक जीवित रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 5.35 करोड़ थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हर 5 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने का खतरा रहता है। लगभग 9 में से 1 पुरुष और 12 में से 1 महिला की मृत्यु इस बीमारी के कारण हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, हृदय रोगों के बाद कैंसर दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है, और इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए, कम उम्र से ही लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कैंसर के मामले और मृत्यु दर बढ़ने की आशंका

अध्ययनों के अनुसार, जिस तरह से कैंसर का खतरा हर साल बढ़ रहा है, आने वाले 20 वर्षों में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2045 तक कैंसर के मामलों में 50: और मौतों में 80: तक वृद्धि हो सकती है। भारत में 2022 में 9.16 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई, और वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2045 तक यह संख्या बढ़कर 17 लाख तक पहुंच सकती है, यानी 20 वर्षों में कैंसर से मौतों की संख्या 80 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

डॉक्टरों का कहना है कि कुछ दशकों पहले की तुलना में अब कैंसर का निदान और उपचार पहले से आसान हो गया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के अधिकतर मामले अंतिम चरण में ही पकड़े जाते हैं, जिससे उपचार मुश्किल हो जाता है और जान बचाने की संभावना कम हो जाती है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि कैंसर को शुरुआती चरण में पहचान लिया जाए, तो 70–80: मामलों में इसे रोका जा सकता है। समय पर निदान और इलाज शुरू होने से कैंसर के शरीर में फैलने को रोका जा सकता है।

कैंसर के लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डॉक्टरों का सुझाव है कि कैंसर के बढ़ते जोखिम को देखते हुए सभी को नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। कैंसर के लक्षणों की पहचान समय पर करना बेहद जरूरी है। शरीर खुद संकेत देता है, जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित लक्षणों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है:

- भोजन निगलने में कठिनाई या लगातार अपच रहना।
- ऐसा घाव जो लंबे समय तक ठीक न हो।
- शरीर के किसी भी हिस्से से बिना वजह खून बहना।
- शरीर में किसी भी हिस्से में गांठ महसूस होना।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी

अध्ययनों के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। हालांकि, सावधानियां बरतकर और टीकाकरण के माध्यम से इससे बचाव संभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में एचपीवी वैक्सीन की दर बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि इस घातक कैंसर के प्रसार को रोका जा सके और वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माणा के पास हुए हिमस्खलन की ली जानकारी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने माणा के पास हुए हिमस्खलन की ली जानकारी राज्य आपात परिचालन केंद्र से व्यवस्थाओं का लिया जायजा अधिकारियों को दिए रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, आई.टी पार्क देहरादून पहुंचकर जनपद चमोली के माणा गांव के पास हुए हिमस्खलन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमस्खलन के बाद रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हिमस्खलन की स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अति शीघ्र घटनास्थल में पहुंचने के निर्देश देते हुए कहा कि घटनास्थल के सबसे समीप स्थित हेलीपैड को अति शीघ्र खोल जाए। जिससे रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा रेस्क्यू अभियान में हेलीकॉप्टर की भी मदद लेकर रेस्क्यू में तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी घायलों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से जरूरत पड़ने पर एम्स ऋषिकेश लाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन से निरंतर समन्वय संपर्क कर उन्हें हर संभव मदद करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जनपद चमोली में हिमस्खलन के बाद लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है। आईटीबीपी, सेना, जिला प्रशासन, वायु सेना, सभी लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सभी से निरंतर वार्ता जारी है। विजिबिलिटी ना होने के कारण वर्तमान में हेलीकॉप्टर का जाना संभव नहीं है। इस संबंध में स्नो एक्सपर्ट की सेवाएं ली जा रही हैं। आईटीबीपी के लोग घटना स्थल में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता श्रमिकों को सुरक्षित निकलना है। सभी लोग अलग अलग स्थानों से हैं, जिसके लिए

हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क में है। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा रेस्क्यू अभियान में किसी भी एजेंसी की आवश्यकता होने पर उनकी मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 लोगों को आईटीबीपी अस्पताल पहुंचाया गया है। बर्फबारी जारी है, कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। कल मौसम खुलने की संभावना है, जिससे रेस्क्यू अभियान में भी तेजी आएगी। सभी रेस्क्यू दल आपस में समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा माणा हेलीपैड को भी एक्टिव किया जा रहा है। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल गोपेश्वर में भी सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से घटना की पूरी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि माणा गांव और माणा पास के मध्य सीमा सड़क संगठन के समीप हिमस्खलन की सूचना मिली थी। यहां सेना की आवाजाही के लिए सड़क मार्ग से बर्फ हटाने वाले मजदूरों के घटना स्थल के समीप होने की जानकारी मिली थी।

जिसके बाद सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरफ, एसडीआरफ की रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री विनय शंकर पांडे, एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

यूक्रेन भड़का सकता है तीसरा विश्व युद्ध-ट्रंप

ट्रंप और जेलेंस्की के बीच शांति समझौते के लेकर हो रही बातचीत जुबानी जंग में बदली, एक-दूसरे पर लगाए आरोप-प्रत्यारोप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को कड़ी फटकार लगाई और उन पर लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।

ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति की नीतियां तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकती हैं। इसके बाद जेलेंस्की बिना किसी महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए।

रूस-यूक्रेन शांति वार्ता अचानक एक जुबानी जंग में तब्दील हो गई। ट्रंप और जेलेंस्की ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किए और तीखी बहस की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने और किसी समझौते पर सहमति बनने के बाद ही वापस लौटने को कह दिया। इसके बाद जेलेंस्की ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में ट्रंप से माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के कारण अमेरिका और यूक्रेन के बीच प्रस्तावित खनिज समझौता रद्द हो गया और जेलेंस्की को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि, एक्स पर उन्होंने ट्रंप को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है।

यूक्रेन-अमेरिका वार्ता की असफलता के बाद जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज को एक विशेष साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्वीकार किया कि यह प्रकरण दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समर्थन वापस लेता है, तो यूक्रेन के लिए रूस से रक्षा करना बेहद कठिन होगा। उन्होंने यह भी दुख जताया कि यह पूरा घटनाक्रम टेलीविजन पर प्रसारित हुआ और अनुरोध किया कि इसे सही किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ट्रंप से माफी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं।

मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, अमेरिकी जनता का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है।ष हालांकि, टीवी कार्यक्रम के अंत में जेलेंस्की ने सामान्य रूप से माफी मांगी, लेकिन ट्रंप के मामले में इससे इनकार कर दिया।

ओवल ऑफिस की बैठक में ट्रंप ने जेलेंस्की को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि उनकी कार्रवाई से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस छोड़ दिया। ट्रंप ने इस समझौते को यूक्रेन को भविष्य में समर्थन देने की एक शर्त बताया था।

लंच रद्द, 10 मिनट की तीखी बहस

ट्रंप, जेलेंस्की और प्रतिनिधिमंडल को एक साथ दोपहर का भोजन करना था, लेकिन यह योजना रद्द हो गई। कर्मचारियों को भोजन की प्लेटें पैक करते हुए देखा गया। इसके अलावा, ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच लगभग 45 मिनट की बैठक हुई, जिसमें अंतिम 10 मिनट काफी गरमागरम बहस में बदल गए। जेलेंस्की ने रूस की कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाए और मास्को द्वारा तोड़ी गई संधियों का हवाला दिया।

तनाव तब बढ़ा जब वेंस ने जेलेंस्की से कहा कि अमेरिकी मीडिया के सामने ओवल ऑफिस में अपने मुद्दों को उठाना अपमानजनक है। इस पर जेलेंस्की ने आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा, ष्आप लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित कर रहे हैं और यह बहुत अपमानजनक है, खासकर उस देश के लिए, जिसने आपको इतना समर्थन दिया है।

ट्रंप ने दी चेतावनी

बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखेगा, लेकिन वह अधिक हथियार नहीं भेजेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए कहा, ष्आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं। वेंस ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए जेलेंस्की से कहा, बस शुक्रिया कहिए। इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी जनता के लिए एक खुलासा करने वाला दृश्य होगा।

ट्रंप ने जेलेंस्की की मंशा पर संदेह जताया

ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल संघर्ष विराम की इच्छा जताई और चेतावनी दी कि यदि जेलेंस्की शांति स्थापित नहीं करते, तो उन्हें अमेरिकी समर्थन खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में, ट्रंप ने मीडिया से कहा, यह व्यक्ति शांति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुरंत युद्धविराम हो। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार हैं, जबकि जेलेंस्की ने अमेरिका को चेतावनी दी कि पुतिन की मंशाओं को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

एचपीवी वैक्सीन

सर्वाइकल कैंसर के खतरे को 80 प्रतिशत तक कम सकती है

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर इस कैंसर के 6.60 लाख से अधिक मामले सामने आए, जबकि भारत में इसी साल 1.27 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हुआ। इतना ही नहीं, 2022 में दुनियाभर में इस बीमारी के कारण 35 हजार से अधिक मौतें हुईं।

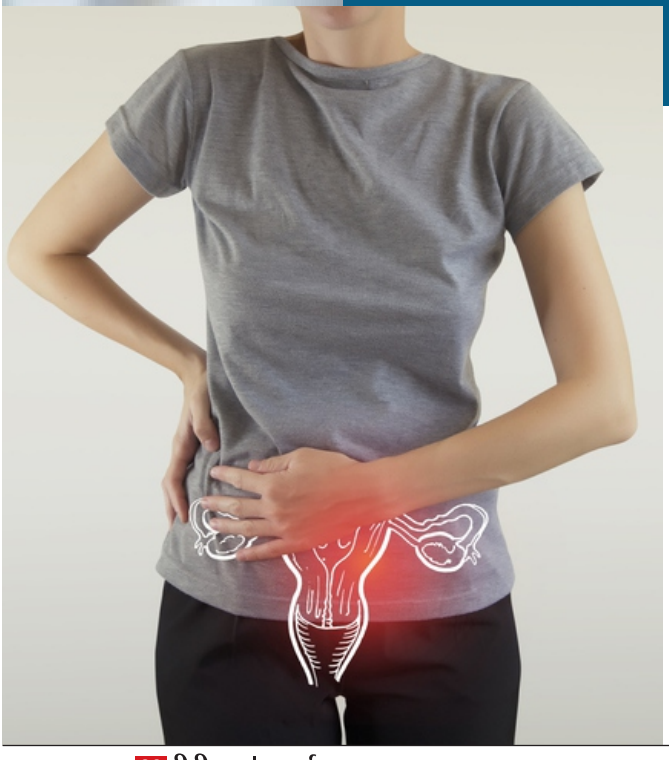

सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौत का चौथा प्रमुख कारण है। अच्छी बात यह है कि कुछ सावधानियां बरतकर और टीकाकरण के जरिए इससे बचाव किया जा सकता है। एचपीवी वैक्सीनेशन को इसमें काफी प्रभावी पाया गया है। सर्वाइकल कैंसर दुनियाभर की महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। हर साल लाखों महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर इस कैंसर के 6.60 लाख से अधिक मामले सामने आए, जबकि भारत में इसी साल 1.27 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हुआ। इतना ही नहीं, 2022 में दुनियाभर में इस बीमारी के कारण 35 हजार से अधिक मौतें हुईं।

अध्ययनों के मुताबिक, महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का यह चौथा प्रमुख कारण है। लेकिन राहत की बात यह है कि सावधानियां अपनाकर और टीकाकरण के माध्यम से इससे बचा जा सकता है। इसी संदर्भ में, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसीपी) ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में एचपीवी वैक्सीन की दर बढ़ाने पर जोर दिया है, जिससे इस घातक कैंसर के प्रसार को रोका जा सके और वैश्विक स्तर पर इससे होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके।

एचपीवी वैक्सीनेशन से कम होता है कैंसर का खतरा

एक सरकारी रिपोर्ट में प्रमाण दिया गया है कि अगर एचपीवी वैक्सीनेशन की दर बढ़ाई जाए, तो यह युवा महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को रोकने में सहायक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2008 से 2022 तक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के दौरान यह पाया गया कि 20–24 वर्ष की महिलाओं में एचपीवी वैक्सीनेशन के कारण प्री–कैंसर स्टेज में होने वाले घाव और अन्य जटिलताओं की दर लगभग 80: तक कम हो गई है। इसका अर्थ है कि यह टीका कैंसर के जोखिम को कम करने में प्रभावी हो सकता है।

एचपीवी वैक्सीनेशन की दर बढ़ाने की सलाह

यह वैक्सीन काफी चर्चा में रही है। 2019 में, एक एंटी–वैक्सीन संगठन शचिल्ड्रन हेल्थ डिफेंसश द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में अमेरिकी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इसे सबसे खतरनाक वैक्सीनष बताया था, जिस पर लगातार बहस होती रही। हालांकि, अब सीडीसीपी ने 27 फरवरी को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में इसे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में प्रभावी बताया है।

सर्वाइकल कैंसर का बढ़ता खतरा

यह जानना महत्वपूर्ण है कि सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में होने वाला कैंसर है, जिसका मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) संक्रमण माना जाता है। यह संक्रमण असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर स्क्रीनिंग टेस्ट और एचपीवी वैक्सीन लगवाने से इस कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों की राय में, 20 वर्ष की उम्र तक की सभी लड़कियों को डॉक्टर की सलाह से एचपीवी वैक्सीन लगवानी चाहिए। अमेरिका में 2006 से 12 साल की लड़कियों को यह वैक्सीन दिए जाने की सिफारिश की जाती रही है। 2011 से, पुरुषों में सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, 12 साल के लड़कों को भी यह वैक्सीन देने की सलाह दी गई है।

वैक्सीनेशन से कैंसर का खतरा कम होता है

कैंसर की रोकथाम पर शोध करने वाली वैज्ञानिक जेन आर. मोंटेलेग्रे का कहना है कि वैक्सीनेशन के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए सभी माता–पिता को यह समझना चाहिए कि एचपीवी वैक्सीन लगवाकर वे अपने बच्चों को भविष्य के गंभीर खतरे से बचा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ–एसईएआर) की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद के अनुसार, 2022 में दक्षिण–पूर्व एशिया में कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यही प्रवृत्ति जारी रही, तो 2050 तक इस क्षेत्र में नए कैंसर मामलों और कैंसर से होने वाली मौतों में 85 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

गार्डासिल 9 वैक्सीन को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसे 9 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जा सकता है। यह वैक्सीन अन्य वैक्सीन के साथ ही दी जा सकती है।

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) 11 या 12 वर्ष की आयु में नियमित एचपीवी टीकाकरण का सुझाव देता है। टीकाकरण के लिए आदर्श आयु, व्यक्ति के यौन रूप से सक्रिय होने से पहले की है।

एक बार जब कोई व्यक्ति भ्च्ट से संक्रमित हो जाता है , तो वैक्सीन उतनी प्रभावी नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैक्सीन का लक्ष्य नए संक्रमण को रोकना है। अगर किसी व्यक्ति में वायरस है, तो वैक्सीन शरीर से वैक्सीन को बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकती है। शोध से पता चला है कि युवावस्था में टीका लगवाने से यौन क्रियाकलाप जल्दी शुरू होने से कोई संबंध नहीं है। 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को 6 से 12 महीने के अंतराल पर दो खुराक दी जा सकती है। जो लोग बाद में, यानी 15 से 26 वर्ष की आयु में वैक्सीन लगवाना शुरू करते हैं, उन्हें वैक्सीन की तीन खुराक लेनी चाहिए। ये खुराक छह महीने में दी जाती हैं।

क्या कहती हैं विशेषज्ञ?

कैंसर की रोकथाम को लेकर अध्ययन करने वाली शोधकर्ता जेन.आर मोंटेलेग्रे कहती हैं, वैक्सीनेशन के परिणामों को देखते हुए सभी माता–पिता को यह भरोसा होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को एचपीवी वैक्सीन देकर उन्हें भविष्य के गंभीर खतरे से बचा रहे हैं।

इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ–एसईएआर) की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद ने एक रिपोर्ट में बताया कि साल 2022 में दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में कैंसर के कई प्रकार के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इसमें सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर भी अलर्ट किया गया था। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर यही गति जारी रहती है तो साल 2050 तक इस क्षेत्र में नए कैंसर के मामलों और इसके कारण मौत में 85 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

शराब की लत की बदौलत 20 साल में दोगुने हो गए लिवर सिरोसिस के मरीज

एम्स के गैस्ट्रोएंटरोल जी विभाग में 25 से 45 साल की उम्र के लिवर सिरोसिस के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। लोगों में बढ़ते शराब के सेवन के कारण विभाग में लिवर सिरोसिस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से कई मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। लिवर से पीड़ित हर दूसरे वयस्क मरीज को शराब की लत होती है। एम्स के एक शोध में यह खुलासा हुआ है

शोध में पाया गया कि पिछले 20 वर्षों में शराब के कारण लिवर सिरोसिस के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है। अध्ययन में शामिल कुल मरीजों में से 43 प्रतिशत मरीजों का लिवर शराब के सेवन से खराब हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, जीवनशैली में बदलाव के कारण शराब पीना आम हो गया है। यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी इससे परहेज नहीं कर रहे। जिन घरों में शराब पीना सामान्य है, वहां के बच्चों में भी यह आदत देखी जा रही है। यही कारण है कि एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में 25 से 45 वर्ष के लिवर सिरोसिस मरीजों की संख्या सबसे अधिक है।

गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि बढ़ते शराब सेवन के कारण लिवर सिरोसिस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और इनमें से कई गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं।

शराब कैसे लिवर को नुकसान पहुंचाती है?

शराब का अधिक सेवन लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लिवर में सूजन (हैपेटाइटिस) हो सकती है। यह लिवर के सामान्य कार्यों को बाधित करता है और समय के साथ स्थायी नुकसान पहुंचाता है। शराब के कारण लिवर में वसा जमने लगता है, जिससे लिवर का सामान्य कार्य प्रभावित होता है और आगे चलकर यह लिवर सिरोसिस (लिवर का सिकुड़ना) का रूप ले सकता है।

बियर भी करती है नुकसान

डॉ. शालीमार के अनुसार, केवल शराब ही नहीं, बल्कि बियर भी लिवर के लिए हानिकारक होती है। ओपीडी में मरीजों से चर्चा के दौरान यह सामने आया कि कई लोग बियर पीते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। उन्हें लगता है कि इससे शरीर को नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत में यह भी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। कुछ लोगों में यह समस्या कुछ ही दिनों में गंभीर हो जाती है, जबकि कुछ मामलों में यह धीरे–धीरे बढ़ती है और तब तक लिवर को भारी नुकसान हो चुका होता है।

43.2 प्रतिशत मामलों में शराब बनी सिरोसिस का कारण

भारत में सिरोसिस का एटियोलॉजिकल स्पेक्ट्रमरू एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा–विश्लेषण विषय पर हुए शोध में देशभर से 41,432 लोगों को शामिल किया गया। कुल 147 शोधों के विश्लेषण से पता चला कि:

- 43.2 प्रतिशत (17,898) मरीजों में लिवर सिरोसिस का कारण शराब थी।
- 11.5 प्रतिशत (4,764) मरीजों में हेपेटाइटिस बी वायरस इसका कारण बना।
- 6.2 प्रतिशत (2,568) मरीजों में हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से सिरोसिस हुआ।
- 14.4 प्रतिशत (5,966) मरीजों में नॉन–अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग या क्रिप्टोजेनिक रोग के कारण सिरोसिस हुआ।

2005 में क्या थे आंकड़े?

भारत में 2005 से पहले शराब के कारण सिरोसिस के मामले लगभग 20 प्रतिशत थे, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण मरीजों की संख्या 22 प्रतिशत से अधिक थी। 2005 से 2022 के बीच किए गए अध्ययन में पाया गया कि पिछले तीन दशकों में शराब से संबंधित लिवर सिरोसिस के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि वायरल संक्रमण से संबंधित सिरोसिस के मामलों में गिरावट आई है।

मेरा पन्ना

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

अबके बरस की होली में

फागुन का महिना आया मस्ती की बहार हो
अबके बरस की होली में सब सपने साकार हो

देवर खेले भाभी संग पीकर भंग धमाल हो
अबके बरस की होली में सब सपने साकार हो

धरती खेले प्रीत रंग में सबको सबसे प्यार हो
अबके बरस की होली में सब सपने साकार हो

भेद-भाव का रंग नही हो सब धर्मो का मान हो
अबके बरस की होली में सब सपने साकार हो

श्याम रंग में रंगी राधिका खेले रंग गुलाल हो
अबके बरस की होली में सब सपने साकार हो

दुश्मन थर्राए भारत से वीरों का सम्मान हो
अबके बरस की होली में सब सपने साकार हो

आर.एन.आई. नं.- RAJHIN/2019/77486

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

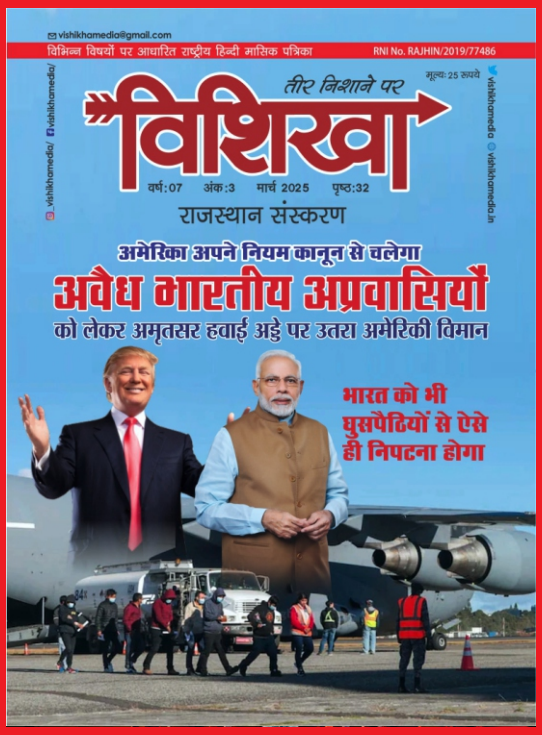

राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद विशिखा

अब शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित...

तीर निशाने पर...
विशिखा

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contactus:+911413562171,9587455444
E-mail:vishikhamedia@gmail.com | Website:www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia